

आने वाले कल
के लिए सबसे
अच्छी तैयारी यही
है कि आज कुछ अच्छा
करें।

- अज्ञात

ब्रेजिट की प्रक्रिया आखिरी चरण में

जॉनसन कह चुके हैं कि अगर नो डील ब्रेजिट होता है तो ब्रिटेन ईयू से ऑस्ट्रेलिया की तरह के व्यापारिक रिश्ते रखेगा, जो एक अच्छी बात होगी। मगर राजनीतिक नफा-नुकसान के गणित को छोड़ दिया जाए तो ब्रेजिट प्रक्रिया में आई यह बाधा ब्रिटेन की आर्थिक मुसीबत को और बढ़ाने वाली है।

बोरिस जॉनसन।।

यूरोपियन यूनियन (ईयू) से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया को फिर झटका लगा है। अभी ब्रिटेन उस एग्जिट समझौते में अपनी तरफ से कुछ काट-छांट करना चाहता है, जिस पर जनवरी में ही दोनों पक्ष दस्तखत कर चुके हैं। हालांकि उसका दावा है कि वह इस समझौते पर अमल को लेकर प्रतिबद्ध है और जो बदलाव वह अपने घरेलू कानूनों में करना चाहता है उसका मकसद कुछ ऐसे स्पष्टीकरणों की राह बनाना भर है, जिससे समझौते पर अमल आसान हो सके। लेकिन चूंकि इस कथित स्पष्टीकरण में समझौते के कुछ प्रावधानों के कमजोर होने की बात है, इसलिए प्रस्तावित छेड़छाड़ पूरे समझौते को ही खतरे में डाल रही है।

ध्यान रहे, ब्रेजिट की प्रक्रिया अपने

आखिरी चरण में है। ब्रिटेन जनवरी में ही ईयू से निकल चुका है लेकिन अमली तौर पर दोनों पक्षों में यथास्थिति बनी हुई है, यानी ईयू के सारे नियम अभी लागू हैं। यह स्थिति संक्रमण काल के दौरान बनी रहेगी, जो इस साल दिसंबर तक चलने वाला है।

बातचीत इस बात को लेकर चल रही है कि उससे पहले नई ट्रेड डील हो जाए ताकि व्यापार से जुड़े तमाम पहलुओं पर किसी तरह की अनिश्चितता न रहे। इस ट्रेड डील के लिए आखिरी समय सीमा 15 अक्टूबर तक की गई है। इसी सिलसिले में बातचीत का अगला दौर लंदन में मंगलवार को तय था। उससे ठीक पहले सोमवार को ही नया विवाद फूट पड़ने के पीछे बातचीत को पटरी से उतारने की मंशा भी बताई जा रही है।

कहा जा रहा है कि 'नो डील ब्रेजिट' मौजूदा हालात में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के लिए सुविधाजनक होगा क्योंकि इससे कोरोना से उपजी अव्यवस्थाओं की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने में उन्हें काफी मदद मिलेगी।

जॉनसन कह चुके हैं कि अगर नो डील ब्रेजिट होता है तो ब्रिटेन ईयू से ऑस्ट्रेलिया की तरह के व्यापारिक रिश्ते रखेगा, जो एक अच्छी बात होगी। मगर राजनीतिक नफा-नुकसान के गणित को छोड़ दिया जाए तो ब्रेजिट प्रक्रिया में आई यह बाधा ब्रिटेन की आर्थिक मुसीबत को और बढ़ाने वाली है। कोई समझौता न हो पाने की स्थिति में ईयू के साथ होने वाला ब्रिटेन का करीब 900 अरब डॉलर का सालाना व्यापार अनिश्चितता के भंवर में पड़ जाएगा।

हालांकि एक राय यह भी है कि ब्रिटिश लीडरशिप के इस अटपटे फैसले के पीछे भी आर्थिक दुश्चिंताओं की बड़ी भूमिका है। ईयू से निकलने के बाद भारत और अन्य कॉमनवेल्थ देशों से व्यापार बढ़ाकर नुकसान की भरपाई करने के मसूबे पूरे होते नहीं दिख रहे। रही-सही कसर कोरोना से उपजी दुश्वारियों ने पूरी कर दी। साल की पहली तिमाही में जीडीपी में आई 20.4 फीसदी की गिरावट तो ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा ही रही है, उससे भी बड़ा संकट यह है कि अर्थव्यवस्था में 'वी' शोप रिकवरी की संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही। लेकिन असल सवाल यह है कि ब्रेजिट पर गुलाटी मारकर लोगों का ध्यान बंटाने की रणनीति उसे कहां ले जाएगी।

शौक पर खर्च करें

अशोक वोहरा।

हो सकता है कि

आपको किसी

प्रकार का अच्छा

शौक हो। जैसे

अगर आप

किसी स्पोर्ट्स

क्लब की

मेम्बरशिप पर

खर्च करें या

ऐसी कोई क्लास

से जुड़ें जिसमें

आपकी गहरी

दिलचस्पी हो तो यह एक अच्छा

चयन होगा। अपनी पसंद का काम

करने पर जो सुकून मिलता है,

उसकी खुशी लंबे समय तक आपके

साथ रहती है और छोटी परिस्थितियों

में आपको टूटने नहीं देती।

कभी कभी तड़के अंधेरे में उठकर

नहा लें और दूर तक अकेले पैदल

पैदल घुमने जाएं। इस दौरान आपन

वृक्षों को, आकाश और बादलों को

अच्छे से निहारें। प्रकृति का भरपूर

आनंद लें और खुद के होने के

अहसास के प्रति भी भर जाएं। यह

आनंद या खुशी आपके जीवन को

बदलने में सक्षम होगी। पैदल चलने

के कई फायदे हैं।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

बच्चों का विकास

सामाजिक संगठनों ने इस बात पर बल दिया कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से आत्मविश्वासी बच्चों का विकास करना है जो अपनी संस्कृति और पारंपरिक प्रथाओं के भरपूर ज्ञान के माध्यम से अपना सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवभारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ी छलांग है। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन इसकी मूल भावना के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने आत्मनिर्भर भारत के लिए इस शिक्षा नीति के रूप में एक आधारशिला रखी है। विभिन्न विद्यालयों से, शैक्षिक संगठनों से हमें यह सुझाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिला कि स्कूल परीक्षाओं के परिणामों का उपयोग केवल विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाए, साथ में निरंतर निगरानी और सुधार के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए। इस विमर्श का ही परिणाम है कि प्रगति कार्ड के माध्यम से हम व्यापक कौशल, संज्ञानात्मक, स्नेह, सामाजिक-भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन पर दिशा केंद्रित कर पाएंगे। चाहे 102 संरचना का प्रतिस्थापन 5334 का विषय हो, नए स्कूल शिक्षा सुधार के साथ रोट लर्निंग दूर करने का विषय हो, गतिविधि-आधारित, प्रायोगिक शिक्षा, कंप्यूटेशनल सोच सीखने की बात हो या पारंपरिक भारतीय मूल्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की बात हो, इन सभी विषयों के बारे में विभिन्न स्रोतों से अनेकानेक सुझाव प्राप्त हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नीति के सफल क्रियान्वयन में सभी हितधारकों का वही सहयोग मिलेगा जो नीति निर्माण के समय मिला था।

हमें पता था कि इस नीति से हमें नवभारत निर्माण की आधारशिला रखनी है। इस संवाद से जहां क्षमता सुधार में सफलता मिली वहीं सबका परामर्श हमारे लिए एक उपयोगी चेक-शीट बना।

सुझावों का व्यापक दायरा

रमेश पोखरियाल निशंक।।

दिल्ली में यूनेस्को की डीजी ने बैठक के दौरान भारत की नई शिक्षा नीति के विषय में उत्सुकतावश पूछा था कि इसमें क्या नया है, तो मैंने उन्हें बताया कि इस नीति की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि हमने इसके निर्माण में मुक्त नवाचार के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े परामर्श के माध्यम से रेकॉर्ड सुझाव लिए। हमने सुनिश्चित किया कि देश के सभी क्षेत्रों से हितधारकों के सुझाव लिए जाएं। हमें पता था कि इस नीति से हमें नवभारत निर्माण की आधारशिला रखनी है। इस संवाद से जहां क्षमता सुधार में सफलता मिली वहीं सबका परामर्श हमारे लिए एक उपयोगी चेक-शीट बना। वैसे भी जनतंत्र में हितधारकों से सार्थक संवाद स्थापित करना जिम्मेदारी से सरकार चलाने के लिए जरूरी है।

यह एक संयोग ही था कि 31 मई 2019 को जिस दिन मैंने मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाला उसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट मुझे सौंपी। नीति पर व्यापक विमर्श करने के लिए मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई। विभिन्न मंचों के माध्यम से मैंने सभी हितधारकों से नीति के मूलभूत स्तंभों—पहुंच, सामर्थ्य, इक्विटी, गुणवत्ता और जवाबदेही



को मजबूत करने के लिए विनम्र निवेदन किया। मेरा प्रारंभ से ही प्रयास रहा कि शिक्षा से जुड़े सभी लोगों से न केवल संवाद स्थापित हो बल्कि उसकी निरंतरता बनी रहे ताकि उनके सुझाव हमें मिल सकें। विमर्श का दायरा बढ़ाने के लिए शैक्षिक जगत से जुड़े संस्थानों से आग्रह किया कि वे नई शिक्षा नीति पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित कर रिपोर्ट से अवगत कराएं। देश में विभिन्न स्थानों पर कुलपतियों के सम्मेलनों/कार्यशालाओं का विशेष आयोजन किया गया। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि नई शिक्षा नीति निर्माण में हमने विश्व का वृहदतम परामर्श किया।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों और

भारत सरकार के मंत्रालयों को ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 पर अपने विचार और टिप्पणियां देने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस ड्राफ्ट का एक सारांश विभिन्न हितधारकों के बीच दिया गया था, जिसका अनुवाद 22 भाषाओं में किया गया। स्कूली शिक्षा और उच्च, तकनीकी शिक्षा के राज्य सचिवों के साथ बैठकें हुईं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुच्चेरी, केरल, कर्नाटक और ओडिशा के माननीय सांसदों के साथ संवाद के माध्यम से उनके विचारों को जानने का प्रयास किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सीएबीई (सेंट्रल अडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन) की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 26 शिक्षामंत्री, उनके प्रतिनिधि, सीएबीई सदस्य, स्वायत्त संगठनों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के कुलपति, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए। विभिन्न हितधारकों से मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दो लाख से अधिक सुझाव आए जिन पर विभिन्न कार्यदलों द्वारा मंथन किया गया।

मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति के ड्राफ्ट एनईपी-2019 पर एक बैठक 7 नवंबर 2019 को आयोजित की गई थी। मुझे जब भी मौका मिला, मैंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शिक्षामंत्रियों से नीति पर चर्चा की।

सूडोकू नवताल-5470				**** सुडोकू			
5	9	1	2	3	8		
		4	5				
2					5		
	3	5		4	8		
7					1		
5	8	6		9			
8							1
		2	9				
3	4	6	7		5	2	

सूडोकू नवताल-5469 का हल								
4	6	2	3	5	8	9	1	7
8	1	7	9	2	6	3	5	4
3	5	9	1	7	4	8	2	6
6	4	1	5	3	7	2	8	9
2	7	5	8	4	9	6	3	1
9	3	8	2	6	1	4	7	5
1	2	3	6	9	5	7	4	8
5	9	4	7	8	2	1	6	3
7	8	6	4	1	3	5	9	2

अपना ब्लॉग सीखने वाले में बदलने का तरीका

मोहन। नई शिक्षा नीति से हम विद्यार्थियों, अध्यापकों, शोधार्थियों और शिक्षकों की सोच में व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं। विज्ञान, गणित और कला क्लबों की स्थापना अधिक जिज्ञासा पैदा करने और एक व्यक्ति को आजीवन सीखने वाले में बदलने का तरीका है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च आउटपुट को एक नए स्तर पर ले जाएगा। संस्थानों के शासन में पूर्व छात्रों की भूमिका शिक्षा प्रणाली को समग्र रूप से प्रभावित करेगी। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि पाठ्यक्रम में समकालीन विषय जैसे—आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरनमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटिजनशिप एजुकेशन आदि शामिल करने के सुझाव हमें देश के कोने-कोने से मिले। मेरा प्रारंभ से ही विश्वास रहा है कि सबके सुझावों पर आधारित गुणवत्तापरक, नवचारयुक्त, प्रौद्योगिकी एवं संस्कारयुक्त नई शिक्षा नीति-2020 एक ऐसा माध्यम बनेगी जिससे भारत अपने खोये हुए वैभव को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा।

